Publication	**The Times of India**	**Language**	English
Edition	New Delhi	**Journalist**	Bureau
Date	12/08/2025	**Page no**	12
CCM	14.83		

Co-op authority holds 1st consultative meet over free and fair polls

Co-op authority holds 1st consultative meet over free and fair polls

New Delhi: The Cooperative Election Authority Monday held its first consultative meeting with state cooperative election bodies, where the issue of whether EVMs can be used in cooperative polls was discussed, among others.

The discussions, held to develop a mechanism to hold free and fair elections in cooperative societies, also took up matters relating to framing of a code of conduct for contesting candidates and Multi-State Cooperative Societies and fixing of an upper limit of expenditure for contesting candidates.

The Cooperative Election Authority, notified in Mar last year as part of multiple reforms in the cooperative sector, has so far conducted 159 elections and is in the process of conducting 69 more cooperative elections. The meeting, helmed by CEA chairperson Devendra Kumar Singh, saw participation of the state poll commissioners from Odisha, Bihar, Tamil Nadu, Telangana and Maharashtra. TNN

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**The Indian Express**	**Language**	English
Edition	New Delhi	**Journalist**	Bureau
Date	12/08/2025	**Page no**	7
CCM	30.61		

CEA seeks to fix upper limit of spending by candidates

CEA seeks to fix upper limit of spending by candidates

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, AUGUST 11

ANNOUNCING THAT it has conducted 159 elections since March 2024, the Cooperative Election Authority said that it wants the upper limit of expenditure by the contesting candidates to be fixed, among other things.

Addressing the first consultative meeting with State Cooperative Election Authorities, CEA Chairperson Devendra Kumar Singh said, "The Cooperative Election Authority has so far conducted 159 elections since March 2024 and is in the process of conducting 69 more such Cooperative Elections."

During the meeting, Singh said that the election process in Cooperative Societies need to be streamlined to foster transparency in order to make the elections in cooperative societies free and fair.

"The Chairperson, Cooperative Election Authority said that there is a need for standard manuals and codes of conduct for cooperative elections. The discussion revolved around matters relating to framing of Code of Conduct for contesting candidates and Multi-State Cooperative Society (MSCs), to fix upper limit of expenditure by the contesting candidates, publication of handbook for the Returning Officers, election of delegates from member Cooperative Societies who are members in National Cooperative Societies and other agenda received from State," the Cooperative Ministry said in a statement.

"One of the agenda proposed by participating State Cooperative Election Authorities included introduction of Electronic Voting Machine in cooperative election," the statement said.

"The CEA decided to hold the consultative committee meeting every three months to take forward the reform process in cooperative elections," the statement said.

The CEA was notified on March 11, 2024, by the Centre under the Multi-State Cooperative Societies Act of 2002. It is responsible for conducting elections of the Multi State Co-operative Society; and supervise, direct and control the matters relating to preparation of electoral rolls.

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**The Hindu**	**Language**	English
Edition	New Delhi	**Journalist**	Bureau
Date	12/08/2025	**Page no**	12
CCM	17.17		

Use of EVMs Suggested for elections in cooperatives

Use of EVMs suggested for elections in cooperatives

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The State Cooperative Election Authorities have proposed to use electronic voting machines (EVM) in cooperative elections, the Union Ministry of Cooperation said on Monday.

The Cooperative Election Authority held its first consultative meeting with the State Cooperative Election Authorities on Monday to develop a mechanism to conduct elections in a free and fair manner.

The meeting chaired by Devendra Kumar Singh, Chairperson of Cooperative Election Authority, saw the participation of State Cooperative Election Commissioners from Odisha, Bihar, Tamil Nadu, Telangana, and Maharashtra. The Cooperative Election Authority has so far conducted 159 elections since March 2024 and is in the process of conducting 69 more elections, Mr. Singh said.

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Hari Bhoomi**	**Language**	Hindi
Edition	New Delhi	**Journalist**	Bureau
Date	12/08/2025	**Page no**	8
CCM	31.58		

Global resonance of cooperation at the UN

यूएन में सहकारिता की वैश्विक अनुगूँज

विश्लेषण
प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

भारतीय सहकारिता की प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र में की जा रही है। हाल में संपन्न हुआ सहकारिता सम्मेलन इसका बड़ा उदहारण है। सहकारिता की संस्कृति की यह वैश्विक अनुगूँज हमारी आर्थिक समृद्धि का कारण बनेगी। एक अच्छी बात यह रही कि हमारे देश के सहकारिता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस साझेदारी को स्वयं संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट सम्मेलन में रखी। उन्होंने बहुत साफ़ शब्दों में कहा कि सहकारिता हजारों वर्ष से भारतीय जीवन मूल्यों की आत्मा रही है। यह साझेदारी पारदर्शिता और सामाजिक न्याय जैसे मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित एक सांस्कृतिक चेतना है जो हमें 'मैं' से 'हम' की ओर ले जाती है।

विश्व में भारत की व्यापक छवि बन रही है। यह भारतीय नागरिकों व सरकार के लिए गर्व की बात है कि सहकारिता मॉडल पर चर्चा करते हुए भारतीय सहकारिता की प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र में की जा रही है। हाल में संपन्न हुआ सहकारिता सम्मेलन इसका बड़ा उदहारण है। सहकारिता की संस्कृति की यह वैश्विक अनुगूँज हमारी आर्थिक समृद्धि का कारण बनेगी साथ ही विश्व में अपनी स्थापनाओं के लिए भी महत्त्वपूर्ण बन सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, दुनिया के लिए सहकारी समितियां एक आदर्श हैं लेकिन भारत के लिए यह हमारी संस्कृति का आधार और जीवन जीने का एक तरीका है। प्रधानमंत्री की वही स्थापना अब संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन से स्वीकार की गई है।

संयुक्त राष्ट्र साझेदारी को प्रोत्साहन देता है। हमारे बहुपक्षीय संबंधों व बहुपक्षवाद की अवधारणाओं के लिए सयुक्त राष्ट्र की पैरवी विगत 80 वर्ष से निरंतर जारी है। सहकारिता के मूल में ही साझेदारी है। कायदे से सहकारिता जैसे उपक्रम को संयुक्त राष्ट्र द्वारा तत्परता व सक्रियता से पूरी पृथ्वी पर फैलाने की भरपूर कोशिश की जानी चाहिए थी। लेकिन विविध विषयों को केंद्र में रखकर आगे बढ़ता संयुक्त राष्ट्र सहकारिता पर उतना सक्रिय राष्ट्रों के बीच एकमत नहीं बना सका। यदि ऐसा कर सका होता तो हमारे साझा भविष्य कुछ ज्यादा समृद्ध हुए होते। समावेशी और सतत कार्रवाई सुनिश्चित करने में अपने विश्वसनीय भागीदार की खोज अब संयुक्त राष्ट्र में भी है। संयुक्त राष्ट्र यह चाहता है कि भारत जैसा लोकतंत्र हमारे साथ खड़ा हो और वह हमारे सहकारिता कार्यक्रम को आगे बढ़ाए।

एक अच्छी बात यह रही कि हमारे देश के सहकारिता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस साझेदारी को स्वयं संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट सम्मेलन में रखी। उन्होंने बहुत साफ़ शब्दों में कहा कि सहकारिता हजारों वर्ष से भारतीय जीवन मूल्यों की आत्मा रही है। यह साझेदारी पारदर्शिता और सामाजिक न्याय जैसे मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित एक सांस्कृतिक चेतना है जो हमें 'मैं' से 'हम' की ओर ले जाती है। जिस प्रकार एक परिवार मिलजुलकर एक दूसरे की भलाई के लिए कार्य करता है, उसी प्रकार सहकारिता भी सामूहिक शक्ति का प्रमाण है। भारत के प्रधानमंत्री ने 'सहकार से समृद्धि' का मंत्र देकर सहकारिता को एक 'जन आंदोलन' का स्वरूप प्रदान किया है। आज यह आंदोलन भारत के कोने-कोने में पहुंचकर हर गांव, हर महिला, हर युवा, हर किसान को सशक्त कर रहा है। वस्तुतः यह समष्टिगत ताकत जो सहकारिता प्रदान कर रही है, उसे अमित शाह ने स्पष्ट किया। गैर-बराबरी मिटाने के लिए सहकारिता का माध्यम इसलिए अब विश्व में जरूरत बनता जा रहा है।

विश्व में गैर-बराबरी के कारण भूख, गरीबी व संघर्ष के विविध स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। यदि भारत में छिड़ा सहकारिता आन्दोलन विश्व के लिए एक मिसाल बन सका तो इसमें अमित शाह का अप्रतिम योगदान इतिहास में अंकित होगा, जिसे उन्होंने कुछ वर्षों में ही भारत में उपलब्धि के रूप में हासिल किया है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वाकांक्षी प्रयास बन सकेगा जो

कि अफ्रीकी देशों में व्याप्त असमानता को दूर कर सकता है। गैर-बराबरी के जख्म को भर सकता है। आर्थिक समृद्धि के लिए नए रोडमैप दे सकता है। भारत का इसलिए यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवदान बनने जा रहा है जो कि सहकारिता आन्दोलन होगा। सहकार से समृद्धि यह नारा ही अपने आप में अद्वितीय है और यह साझेदारी से समृद्धि की नई चेतना का विस्तार है।

सहकारी समितियों की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि वे लोकतांत्रिक होती हैं। वे जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित संस्थाएँ हैं। ये विशेषताएँ अपने आप में सहकारी समितियों को सतत विकास का एक आदर्श माध्यम बनाती हैं, जो वास्तव में लोगों की जरूरतों को प्रतिबिंबित और पूरा करती हैं। सबसे अहम बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र में हुए सम्मेलन में केन्या, कोलंबिया व मंगोलिया के राजदूत ने भारत की खूब तारीफ़ की। अगर केन्या के राजदूत के उद्बोधन का स्मरण करें तो उन्होंने कहा कि अच्छे रोजगार सृजित करने के अलावा, सहकारी समितियाँ पारंपरिक रूप से बहिष्कृत समूहों जैसे महिलाओं, युवाओं, वृद्धों, विकलांग व्यक्तियों और स्वदेशी लोगों के लिए परिणामों में सुधार करके सामाजिक समावेशन और भूख व गरीबी उन्मूलन में भी योगदान देती हैं। भारत का एक आदर्श उदाहरण सामाजिक-एकजुटता व एकजुट अर्थव्यवस्था की सफलता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने की दिशा में इसे प्रदर्शित करता है।

सच यह है कि भारत की जनसँख्या इन्डियन डिविडेंड है। भारत में अभी 840,000 से ज्यादा सहकारी समितियाँ हैं जिनके 32 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। यह संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, भारत के सहकारिता को बल मिलेगा। भारत में अभी एक सहकारिता विश्वविद्यालय है, आने वाले समय में इसकी संख्या जब कम से कम पांच हो जाएगी, तो भारत का सहकारिता मानव संसाधन पूरे विश्व में सर्वोत्तम परिणाम दे सकेगा। हमारे देश की लीडरशिप आज इतनी मजबूत है जो इसे करेगी भी। बेहतर दुनिया बनाने हेतु सच में संकल्प से सिद्धि एक माध्यम है। भारत की लीडरशिप इसके लिए सतत प्रयास कर रही है। आज जब एसडीजी-2030 के लक्ष्य को वैश्विक स्तर पर हासिल करने की बात की जा रही है तो भी भारत की ओर दुनिया रुख कर रही है। आईएलओ की प्रतिनिधि ने भारत की प्रशंसा इस बात पर की कि भारत ने सहकारिता व सहकारी समितियों को पहचाना। उसने इसे महत्व दिया व इसे एकजुट किया। भारत में सहकारिता को प्रमुखता दी जा रही है, इसे गरीबी उन्मूलन के उपादान के तौर पर प्रतिष्ठित की जा रही है। यही कारण है कि इसकी संयुक्त राष्ट्र में अनुगूँज सुनाई पड़ रही है। इस प्रशंसा से यह एहसास होता है कि सच में भारत ने कुछ किया है, कुछ विशेष अचीव किया है।

विश्व में अभी प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नए युग के लिए संभावित कदमों की पहचान करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर विचार किया जा रहा है। अभी भी विश्व के सभी देश सहकारिता को अपने देश के विकास का हिस्सा नहीं मान रहे हैं, अपितु वे यह विश्वास कर रहे हैं कि वे अचानक से वह सब हासिल कर लेंगे जो सहकारिता के बिना भी संभव है। भारत का अभिप्राय है ही है कि वह सम्पूर्ण विश्व को प्रभाषित करके सबको विकास व आत्मबोध के प्रकाश से भर दे। यदि विश्व में सहकारिता के विकास के लिए भारत सरकार सहकारिता पैरोकारों को तैनात करे तो निश्चय ही यह उसकी ओर से वैश्विक बदलाव की दिशा में अप्रतिम व महत्वाकांक्षी योजना सिद्ध होगी। इससे विश्व में सहकारिता के लिए भारत की देशों के स्वभाव परिवर्तन की एक नई गाथा ऐतिहासिक रूप से अंकित होगी।

(लेखक राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में सेवर प्रोफेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

****

Downloaded from
SAMVAD